



CRUDE WATCH

OIL SLIPS FIRST TIME IN THREE WEEKS

Houston: Oil prices rose on Friday as US buyers covered positions on worries over US-Iran nuclear talks, but declined for the first time in 3 weeks. Brent crude futures rose 0.54% on Friday to close at \$64.78 per barrel, while US WTI crude were up 0.54% to \$61.53/barrel. **REUTERS**

 **The Indian EXPRESS**
JOURNALISM OF COURAGE

Sun, 25 May 2025
[https://epaper.indian](https://epaper.indianexpress.com)



Trend flattens

CRUDE CHECK. Bullish bias remains

Akhil Nallamuthu

bl. research bureau

Crude oil prices moderated last week. Brent crude oil futures on the Intercontinental Exchange (ICE) (\$64.80/barrel) lost 1 per cent. Whereas the crude oil futures on the MCX (₹5,259/barrel) was down 1.3 per cent.

BRENT FUTURES (\$64.80)

The recovery that the Brent crude oil futures has been witnessing since the beginning of this month, appears to have hit a wall. The price action shows that the contract is struggling to get over the barrier at \$66. Just above this is another hurdle at \$68.

A clear breakout of \$68 can turn the outlook positive. In this case, Brent crude oil futures can rise to \$75, a resistance. Above this, the nearest resistance is \$82.

If the contract slips below \$63, it can fall further to \$60 and then \$58.50, notable support levels.

MCX-CRUDE OIL (₹5,259)

Crude oil futures (June) remains above the 21-day moving average, which is now at ₹5,170. However, for nearly two weeks, it has been struggling to extend the



rally as ₹5,500 has been acting as a strong roadblock. Similarly, ₹5,170 has been providing support to the contract, preventing a decline beyond this.

A breakout of ₹5,500 can give bulls more control where they can lift crude oil futures to ₹6,100. A rally past this hurdle can take the contract to ₹7,000.

On the other hand, if the contract falls from the current level and declines below the nearest support at ₹5,170, we might see another leg of downtrend. In this case, crude oil futures can retest the support at ₹4,750. But note that there is a support above this at ₹5,000.

Trade strategy: Traders can buy crude oil futures if it breaks out of ₹5,500. Place stop-loss at ₹5,200 initially and revise it to ₹5,600 when the contract touches ₹5,800. Book profits at ₹6,100.

देश में बायो एविएशन फ्यूल के पहले प्लांट की स्थापना की ओर बढ़ाया कदम

सुमन सेमवाल • जागरण

देहरादून : बायोफ्यूल (जैव ईंधन) के क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आइआइपी) द्वारा विकसित बायोफ्यूल तकनीक के आधार पर मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स (एमआरपीएल), कर्नाटक ने बायोफ्यूल के प्लांट की स्थापना का कार्य आरंभ कर दिया है। प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 70 टन होगी और इसके लिए 450 से 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। प्लांट को वर्ष 2027 तक स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारत के लिए बायोफ्यूल उत्पादन की दिशा में 27 अगस्त 2018 का दिन ऐतिहासिक है, जब देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट से स्पाइस जेट के विमान ने बायोफ्यूल से दिल्ली तक उड़ान भरी थी। इसके बाद से आइआइपी ने इसके व्यावसायिक उत्पादन के लिए बड़ी कंपनियों की खोज शुरू की थी, जिसमें पहला नाम एमआरपीएल का आया। आइआइपी के निदेशक डा. हरेंद्र के

अनुसार, यह प्लांट वेस्ट कुकड आयल से बायोफ्यूल तैयार करेगा। जेट्रोफा के बीजों से भी तेल निकालकर बायोफ्यूल का उत्पादन किया जाएगा। बायोफ्यूल का उपयोग सामान्य ईंधन में मिश्रण के रूप में किया जाएगा, जिसमें इसे 50 प्रतिशत तक मिलाने की अनुमति है, पहले चरण में एक प्रतिशत के मिश्रण की सिफारिश की गई है। प्रतिदिन 70 टन बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए 150 टन वेस्ट कुकिंग आयल की आवश्यकता होगी।

इस बायोफ्यूल की वर्तमान लागत लगभग 120 रुपये प्रति लीटर है, लेकिन इसे सामान्य ईंधन के स्तर पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

15 प्रतिशत कम होगा कार्बन उत्सर्जन : एविएशन सेक्टर के विकास के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन की चिंता भी बढ़ी है। बायोफ्यूल को बढ़ावा देने से कार्बन उत्सर्जन को 15 प्रतिशत तक कम किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने 2015 में पेरिस समझौते में यह आश्वासन दिया था कि वर्ष 2030 तक कार्बन सिंक की क्षमता 2.5 से 3 बिलियन टन तक बढ़ाई जाएगी।

भारत ने प्रतिकूलताओं के बावजूद ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम किया : पुरी

- सरकार ने दो बार उत्पाद शुल्क में की कटौती
- एलपीजी की खपत में शानदार वृद्धि दर्ज
- प्रतिदिन 56 लाख सिलेंडरों की हुई डिलीवरी

नई दिल्ली, 24 मई (एजेंसियां)। केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने, एलपीजी कवरेज का विस्तार करने और देशभर में रिफाइनिंग और वितरण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सक्रिय उपायों के बारे में जानकारी दी।

हरियाणा के मानेसर में मंत्रालय की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, केन्द्रीय मंत्री पुरी ने विस्तार से बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत भू-राजनीतिक प्रतिकूलताओं से पार पाते हुए नागरिकों के लिए बिना किसी कमी के ऊर्जा की वहनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करने में सफल रहा। विशेष रूप से, सरकार ने दो बार उत्पाद शुल्क में कटौती की, जिसमें पहली कटौती 4 नवंबर, 2021 को और दूसरी कटौती 22 मई, 2022 को पेट्रोल पर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 16 रुपये प्रति लीटर के रूप में की गई। अप्रैल 2025 में की गई हालिया बढ़ोतरी को तेल विपणन कंपनियों ने



वहन कर लिया, जिससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ से बचाया जा सके। एलपीजी सुधारों पर प्रकाश डालते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। इसकी शुरुआत के बाद से, एलपीजी कवरेज 2014 में 55 प्रतिशत से बढ़कर आज लगभग सार्वभौमिक पहुंच तक पहुंच गया है। एलपीजी की खपत में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें प्रतिदिन 56 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी हुई है। अब देश भर में 25,000 से अधिक एलपीजी वितरक काम कर रहे हैं, जिनमें से 86 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि भारत में एलपीजी की कीमतें वैश्विक स्तर पर सबसे कम हैं।

भारत ने भू-राजनीतिक प्रतिकूलताओं के बावजूद ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम किया: केन्द्रीय मंत्री

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने, एलपीजी कवरेज का विस्तार करने और देशभर में रिफाईनिंग और वितरण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सक्रिय उपायों के बारे में जानकारी दी।

हरियाणा के मानेसर में मंत्रालय की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, केन्द्रीय मंत्री पुरी ने विस्तार से बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत भू-राजनीतिक प्रतिकूलताओं से पार पाते हुए नागरिकों के लिए बिना किसी कमी के ऊर्जा की वहनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करने में सफल रहा। विशेष रूप से, सरकार ने दो बार उत्पाद शुल्क में कटौती की, जिसमें पहली कटौती 4 नवंबर, 2021 को और दूसरी कटौती 22 मई, 2022 को पेट्रोल पर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 16 रुपये प्रति लीटर के रूप में की गई। अप्रैल 2025 में की



गई हालिया बढ़ोतरी को तेल विपणन कंपनियों ने वहन कर लिया, जिससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ से बचाया जा सके।

एलपीजी सुधारों पर प्रकाश डालते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। इसकी शुरुआत के बाद से, एलपीजी

कवरेज 2014 में 55 प्रतिशत से बढ़कर आज लगभग सार्वभौमिक पहुंच तक पहुंच गया है। एलपीजी की खपत में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें प्रतिदिन 56 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी हुई है। अब देश भर में 25,000 से अधिक एलपीजी वितरक काम कर रहे हैं, जिनमें से 86 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि भारत में एलपीजी की कीमतें वैश्विक स्तर पर सबसे कम हैं। अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में 58 प्रतिशत की भारी वृद्धि के बावजूद, पीएमयूवाई उपभोक्ता अब 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए केवल 553 रुपये का भुगतान करते हैं। एलपीजी की कीमतें किफायती रखने के लिए तेल कंपनियों को पिछले साल 40,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। लगभग 1,058 रुपये की कीमत वाला सिलेंडर पीएमयूवाई लाभार्थियों को मात्र 553 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। नियमित उपभोक्ताओं के लिए, कीमत 853 रुपये है।